(ख) उन नक्सलवादियों में से कितनों पर मुकदमें चलाए गए ; और

(ग) इस अवधि में नक्सलवादियों द्वारा हिंसा की कितनी घटनाएं की गईं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 1969 में 1338, 1970 में 708 तथा 1971 में अब तक 52 नक्सलवादियों तथा अन्य उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में 1750 नक्सलवादियो तथा अन्य उग्रवादियो पर मुकदमा चलाया गया। उक्त अवधि में नक्सलवादियो तथा अन्य उग्रवादियो द्वारा 290 अपराध किए गये

Naxalite Activities in Srinagar Valley

*64. SHRI P. K. DEO : Will the Minister of HOME AFFAIRS (GRIH MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the Naxalite activtties have been recently on the increase in the Srinagar valley ;

(b) whether they have in the recent past initiated numerous sabotage activities ; and

(c) if so, the action, if any, taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFSAIRS (GRIH MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

Resignation by Members of Yojana Ayog

*67. SHRI R. R. SINGH DEO : Will the Minister of PLANNING (YOJNA MANTRI) be pleased to state :

(a) whether all the Members of the Yojana Ayog including its former Deputy Chairman recently resigned from their respective offices ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) to (c). With the formation of a new Government after the General Elections, the former, Deputy Chairman and Members of the Planning Commission submitted their resignations, so that the Government would be free to reconstitute the Commission.

Grant of Pension to Freedom Fighters in Kerala

*70. SHRI R. KANDANPALLI : Will the Minister of HOME AFFAIRS (GRIH MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the Kerala Government have taken any decision for granting pension to freedom fighters in the State ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). The Government of Kerala have informed us that they have sanctioned a scheme for the grant of pension to freedom fighters. Statement containing a note giving the salient features of the scheme is laid on the Table of the House.

Statement

The Government of Kerala have sanctioned a scheme for the grant of pension to freedom fighters who had participated in the National Movement for the emancipation of the country till 15th August 1947. The scheme is also applicable to ex-I.N.A. personnel and to those who had participated in the Goa liberation Movement and the liberation of Mahe from French Rule.

2. "Freedom Fighter" for the purpose has been defined as a person who (a) had been sentenced to imprisonment for not less than 6 months, or (b) had been kept under detention (including detention as under-trial prisoner) for not less than 6 months, or (c) was killed in action, or (d) was sentenced to death, or (e) died due to the Police or Military firing or lathicharge, or (f) lost his/her job or means of livelihood or the whole or a substantial part of his/her property, or (g) became permanently incapacitated due to such participation or affected with grave disease for life.

3. The amount of pension is Rs. 50 per mensem, and is payable either to a freedom fighter or his widow or minor children whose annual income from all sources including help from near relatives does not exceed Rs. 300 per mensem. The pension is payable during the life-time of the freedom fighter and in the case of his widow for her life time or till re-marriage.

4. An Advisory Committee will be constituted in each district consisting of old freedom fighters who command respect among the people, preferably those who had participated in the 1930 or 1942 movements, and in Malabar in the 1938 Movement in Travancore etc.

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद

*73. **श्री प्रताप सिंह नेगी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक पहाड़ी विकास परिषद कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के विकास हेतु उक्त परिषद् द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त परिषद् द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान किये जाने वाले कार्य का पूरा ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) बोर्ड पहाड़ी जिलों के लिए योजनायें बनाता रहेगा तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसकी कार्यान्विति पर भी नजर रखेगा।

विवरण

अब तक, पुनर्गठित बोर्ड की मीटिंग दो बार हुई है—अक्तूबर, 1969 में तथा दिसम्बर, 1970 में। अब तक बोर्ड ने जो कार्य किया है वह इस प्रकार है :—

(1) वार्षिक योजना 1970-71 पर विचार किया तथा विभिन्न विकास खण्डों के लिये परिव्ययों की सिफारिश की।

(2) पर्वतीय जिलों के पारस्परिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने तथा 1970-71 में अनेकों पर्वतीय जिलों में एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय का वितरण करने की सिफारिश करने का निर्णय किया है।

(3) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये संस्थागत वित्त प्राप्ति हेतु एक विकास निगम की स्थापना करने की सिफारिश की। अब यह निगम स्थापित किया जा चुका है। इसका मुख्यालय नैनीताल में है।

(4) पर्वतीय जिलों में विकास की आवश्यकताओं पर विचार करने तथा उनकी जांच करने और राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने वाले कार्यक्रमों तथा उनमें प्राथमिकताओं का निर्धारण करने और उसी साहस्य पर पर्वतीय विकास की योजना भी बनाने के लिये एक योजना उप-समिति का गठन किया। तदनुसार 29-3-1971 को राज्य सरकार द्वारा एक उप-समिति का गठन किया गया जिसमें सभी संसद-सदस्य, जिला परिषदों के अध्यक्ष (आजकल जिलाधीश जो कि जिला परिषदों के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं) तथा पर्वतीय जिलों के आयुक्त और 8 पर्वतीय जिलों में से प्रत्येक का एक विधायक सदस्य था।